भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1864
गुरूवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

अवसंरचना क्षेत्र में रोजगार के अवसर

1864. डा. फौजिया खानः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अवसंरचना क्षेत्र में उच्च वृद्धि, नए संगठन की स्थापना और रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों के सृजन की वृहद संभावनाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा और नाम क्या हैं;

(ग) सरकार के स्तर पर अवसंरचना क्षेत्रों का संवर्धन करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में रोजगार अवसरों की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़ों का स्रोत होता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग जिसका तात्पर्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रोजगार से है, द्वारा कामगारों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित प्रतिशत वितरण, इस प्रकार है:

एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22
खनन और उत्खनन	0.3	0.3	0.3
उत्पादन	11.2	10.9	11.6
विद्युत, जल, आदि	0.6	0.6	0.6
विनिर्माण	11.6	12.1	12.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़े दर्शाते है कि उपरोक्त प्रमुख उद्योगों में पिछले तीन वर्षों में रोजगार में वृद्धि हुई है। निर्माण क्षेत्र में कामगार का प्रतिशत वर्ष 2019-20 में 11.6% की तुलना में वर्ष 2021-22 में बढ़कर 12.4% हो गया है।

इसके साथ-साथ, श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्रमिक तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन करना है। चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार, नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार 3.18 करोड़ था, जो क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल--जून, 2021) के अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 10 लाख अधिक है। चयनित नौ क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार में से, विनिर्माण क्षेत्र में 38.5% और निर्माण क्षेत्र में 1.9% का योगदान है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****